



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 234 ]  
No. 234 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 1996/श्रावण 4, 1918  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 1996/SRAVANA 4, 1918

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1996

सा.का.नि.336(अ):—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति विनियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं :

2. इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "अधिनियम" से 1987 का विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (संख्या 39) अभिप्रेत है;
- (ख) "केन्द्रीय प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) "अध्यक्ष" से उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (घ) "समिति" से उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है।

(ङ) "विधिक सेवा अधिवक्ता" से ऐसा अधिवक्ता अभिप्रेत है जिसे विधिक सेवा से संबंधित कोई काम समनुदिष्ट किया गया है।

(च) "विधिक सेवा काउंसिल एवं परामर्शदाता से ऐसा अधिवक्ता अभिप्रेत है" जो समिति द्वारा विधिक सेवा काउंसिल एवं परामर्शदाता के रूप में नियुक्त है।

(छ) "सदस्य" से समिति का सदस्य अभिप्रेत है।

(ज) "सचिव" से अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समिति का सचिव अभिप्रेत है।

निहित होने का साधारण प्रभाव

3. इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख को और से -

- (1) पूर्ववर्ती उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति की समस्त आस्तियां, दायित्व, अधिकार, हक और हित उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को अंतरित तथा में निहित हो गए हैं;
- (2) जो कर्मचारियों पूर्ववर्ती उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति में काम कर रहे हैं, इस उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के लिए काम करने वाले समझे जाएंगे;
- (3) समिति विधिक सहायता पैल वकीलों द्वारा अपनी वृत्तिक सेवाओं के लिए प्रस्तुत किए गए फीस बिलों का तथा अन्य समस्त देयों का जो पूर्ववर्ती उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति द्वारा उपगत हैं और उसके समक्ष लम्बित हैं, सत्पादन करने के बाद संदाय करेगी;

- (4) समिति पूर्ववर्ती उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति की उत्तराधिकारी बनेगी और जहां तक भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष चले मामलों में विधिक सहायता देने का संबंध है, पूर्ववर्ती उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति द्वारा दिए गए सभी वायदों को पूरा करेगी। उच्चतम न्यायालय (मध्य आय समूह) विधिक सहायता समिति की कोई आस्ति या दायित्व समिति पर न्यागत नहीं होगा, किन्तु समिति अपने स्थापन की ऐसी विधियों का विस्तार उक्त उच्चतम न्यायालय (मध्य आय समूह) विधिक सहायता समिति तक कर सकेगी जिन का अनुमोदन अध्यक्ष द्वारा किया जाए।

#### समिति के सदस्यों का कार्यकाल और उनसे संबंधित अन्य शर्तें

4. (1) पदेन सदस्य से भिन्न समिति के सदस्य की पदावधि दो वर्ष होगी।
- (2) जहां कोई व्यक्ति पदेन सदस्य नामनिर्दिष्ट किया जाए, वहां ऐसा व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह उस पद को धारण करना बंद कर देता है जिसके फलस्वरूप वह पदेन सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है।
- (3) समिति के सदस्य के पद पर कोई रिक्ति उसी रीति से भरी जाएगी जैसे मूलतः नियुक्त सदस्य की भरी जाती है और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस सदस्य के कार्यकाल की जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, शेष अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा।
- (4) पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य दो पदावधियों से अनधिक के लिए नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

#### समिति की शक्तियां और कृत्य

##### 5. समिति की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

- (क) भारत के उच्चतम न्यायालय के संबंध में विधिक सेवा कार्यक्रम का प्रशासन और कार्यान्वयन करना तथा इस प्रयोजन के ऐसे सभी कदम उठाना जो आवश्यक हों और केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना;
- (ख) विधिक सेवाओं के लिए आवेदन प्राप्त करना और उनकी संवीक्षा करना तथा विधिक सेवा देने या वापस लेने के बारे में सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना;
- (ग) विधिक सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय में अभिलेख अधिवक्ताओं के तथा ज्येष्ठ अधिवक्ताओं के पैगल रखना;
- (घ) उच्चतम न्यायालय के अभिलेख अधिवक्ताओं और ज्येष्ठ अधिवक्ताओं को विधिक सेवाओं के लिए मानदेय, खर्च, प्रभार और व्यय अदा करने से संबंधित सभी मामलों का विनिश्चय करना;
- (ङ) विधिक सेवा कार्यक्रम के बारे में विवरणियां, रिपोर्टें और आंकड़ों की जानकारी तैयार करना तथा केन्द्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत करना;

#### अध्यक्ष के कृत्य और शक्तियां

6. (1) समिति का अध्यक्ष समिति के कार्यक्रमों के प्रशासन और कार्यान्वयन का सम्पूर्ण प्रभारी होगा;

परन्तु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को विधिक सेवा देने या वापस लेने से संबंधित किसी प्रश्न से प्रत्यक्षतः अपना संबंध नहीं रखेगा;

(2) अध्यक्ष तीन मास की अवधि में कम से कम एक बार समिति की बैठकें सचिव के माध्यम से आयोजित करवाएगा।

(3) अध्यक्ष समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(4) अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त होंगी।

#### सचिव की पदावधि और सेवा की शर्तें

7. (1) सचिव की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(2) सचिव ऐसा मानदेय प्राप्त करने के लिए हकदार होगा जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाएगा।

(3) सचिव को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।

#### सचिव के कृत्य और शक्तियां

8. (1) सचिव समिति का प्रधान अधिकारी होगा तथा समिति के नियंत्रणाधीन समस्त आस्तियों, लेखाओं, अभिलेखाओं और निधियों का अभिरक्षक होगा।

(2) सचिव समिति की प्राप्तियों का, उसकी निधियां के संचितरण का सही और उचित लेखा रखेगा या रखवाएगा।

(3) सचिव अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से समिति की बैठकें आयोजित करेगा और बैठकों में भाग भी लेगा तथा बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त का अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

#### समिति की बैठकें

9. (1) समिति तीन मास में कम से कम एक बार ऐसी तारीख को और ऐसे स्थान पर बैठक करेगी जो अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(2) अध्यक्ष समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया व्यक्ति समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त सचिव द्वारा सही और ठीक ढंग से रखा जाएगा और ऐसी कार्यवृत्त का निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा और युक्तियुक्त समय पर किया जा सकेगा। कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि बैठक के बाद यथाशक्य शीघ्र केन्द्रीय प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष को भेजी जाएगी।

(4) बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष सहित चार होगी।

(5) समिति की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा बहुमत से किया जाएगा और बराबर-बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

#### समिति की निधियां, संपरीक्षा और लेखा

10. (1) समिति एक निधि रखेगी जिसे उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति निधि कहा जाएगा जिसमें निम्नलिखित राशियां जमा की जाएंगी :—

- (क) ऐसी रकमें जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा ठसे आबंटित की जाएं और दी जाएं;
- (ख) संदान के रूप में समिति द्वारा प्राप्त ऐसी समस्त रकमें;
- (ग) उन व्यक्तियों को जिन्हें विधिकसेवा प्रदान की गई है या विरोधी पक्षकार से वसूल की गई खर्च, प्रभार और व्यय के रूप में ऐसी समस्त रकमें।

(2) उक्त निधि में जमा सभी राशियां एक राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाएंगी।

स्पष्टीकरण :—उप विनियमन में राष्ट्रीयकृत बैंक से तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में परिभाषित है।

(3) आकस्मिक छुटपुट प्रभारों को पूरा करने के प्रयोजन के लिए जैसे न्यायालय शुल्क, स्टाम्प तथा दस्तावेजों आदि की प्रतिलिपियां अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यय, दो हजार पांच सौ रुपये की स्थायी अग्रिम राशि समिति के सचिव के नियंत्रण में रखी जाएगी।

(4) विधिक सेवा समिति की वास-सुविधा और कर्मचारिवृंद का समस्त व्यय एवं समिति के विभिन्न कृत्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय, समिति की निधियों में से तथा अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से किया जाएगा।

(5) समिति की निधियों का उपयोग समिति या अध्यक्ष या अन्य सदस्यों द्वारा या सचिव द्वारा विधिक सेवा क्रियाकलापों के संबंध में की गई यात्राओं पर या ठपगत या के अनुषंगी व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा। अध्यक्ष, पदेन सदस्यों और सचिव को संदेय यात्रा-भत्ता और मंहगाई भत्ता उतना होगा जितने के लिए वे अपने-अपने द्वारा धारित पदों के फलस्वरूप हकदार हैं।

(6) समिति का सचिव और इस प्रयोजन के लिए अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित समिति का एक सदस्य संयुक्त रूप से अध्यक्ष के निर्देशानुसार समिति के बैंक लेखाओं का संचालन करेंगे।

(7) समिति समस्त प्राप्तियों और संवितरणों का सही-सही लेखा रखवाएंगी और केन्द्रीय प्राधिकरण को तिमाही विवरणियां पेश करेगी।

(8) समिति को लेखाओं की संपरीक्षा हर वर्ष अर्हित संपरीक्षक द्वारा की जाएगी और केन्द्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे।

#### विधिक सेवाओं के लिए आवेदन

11. (1) उच्चतम न्यायालय में कोई कार्यवाही लाने या उसकी प्रतिरक्षा करने के लिए विधिक सेवा के लिए पात्र कोई व्यक्ति इस निमित्त लिखित आवेदन कर सकेगा, फिर भी यदि आवेदक निरक्षर है या लिखने की स्थिति में नहीं है तो सचिव या समिति का कोई अधिकारी उसके मौखिक निवेदन लेखबद्ध करेगा/अभिलेख पर उसके अंगूठे की छाप/हस्ताक्षर लेगा और ऐसा अभिलेखा उसका आवेदन माना जाएगा।

(2) समिति आवेदनों का एक रजिस्टर रखेगी जिसमें विधिक सेवाओं के सभी आवेदन तारीखवार दर्ज और रजिस्टर किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदनों पर की गई कार्यवाहियां ऐसे आवेदन से संबंधित प्रविष्टि के सामने अंकित की जाएंगी।

#### आवेदनों का निपटारा

12. (1) विनियमन 11 में वर्णित विधिक सेवाओं के लिए आवेदन

करने पर सचिव सबसे पहले नियमों के साथ पठित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आवेदक की पात्रता की जांच पड़ताल और निर्धारण करवाएगा।

(2) यदि आवेदक पात्रता कसौटियों पर खरा उतरता है तो सचिव उसके आवेदन के गुणागुण पर विचार करने के लिए अग्रसर होगा। आवेदन के गुणागुण की जांच-पड़ताल करने के लिए सचिव विधिक सेवा अधिवक्ताओं की या ऐसे अन्य अधिवक्ताओं की जो निःशुल्क विधिक सेवा देने के लिए इच्छुक हैं, सहायता ले सकेगा। सचिव समिति द्वारा नियोजित विधिक सेवा काउंसिल एवं परामर्शदाता की सलाह भी ले सकेगा। यदि किसी विशेष मामले में गहरी जांच-पड़ताल आवश्यक है तो सचिव एक से अधिक राय प्राप्त करने से विरत नहीं होगा।

(3) यदि आवेदक पात्रता कसौटी पात्रता पर खरा उतरता है और उसके आवेदन में सार भी है तो सचिव विधिक सेवा के ढंग का विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगा।

(4) किसी भी मामले में विधिक सेवा की मंजूरी के लिए आवेदन, यदि वह उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो, सचिव द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से नामंजूर किया जा सकेगा।

(5) विधिक सेवा देने से इंकार करने की दशा में सचिव आवेदक को ऐसी इंकारी की लिखित रूप में जानकारी देगा।

(6) आवेदक जिसका विधिक सेवा की मंजूरी का आवेदन नामंजूर कर दिया गया है, अध्यक्ष के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए अपील कर सकेगा।

#### विधिक सेवाओं के ढंग

13. प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक शामिल हो सकेगी :—

- (क) किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में संदेय या ठपगत न्यायालय फीस, आदेशिका फीस और अन्य सभी प्रभारों का संदाय;
- (ख) किसी विधिक कार्यवाही के प्रारूपण के लिए, तैयारी करने के लिए और फाइल करने के लिए एवं विधिक कार्यवाही में विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रभार;
- (ग) निर्णयों, आदेशों और विधिक कार्यवाहियों में अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां अभिप्राप्त करने और प्रदाय करने का खर्च;
- (घ) विधिक कार्यवाहियों में पेपर-बुक (जिसमें दस्तावेजों का कागज, मुद्रण और अनुवाद शामिल है) तैयार करने की लागत तथा उसके आनुषंगिक व्यय।

#### कुछ मामलों में विधिक सेवा न दी जानी

14. निम्नलिखित मामलों में विधिक सेवा नहीं दी जाएगी, अर्थात :—

- (1) निम्नलिखित की बाबत पूर्णतया या भागतः कार्यवाहियां—
  - (क) मान हानि; या
  - (ख) विद्वेषपूर्ण अभियोजन; या
  - (ग) न्यायालय कार्यवाही की अवमानना से आरोपित व्यक्ति; या
  - (घ) शपथ भंग;
- (2) किसी निर्वाचन से संबंधित कार्यवाहियां।

- (3) उपविनियमन (1) और (2) में निर्दिष्ट किन्हीं कार्यवाहियों की आनुवंशिक कार्यवाहियाँ।
- (4) उन अपराधों की बाबत कार्यवाहियाँ जिनमें अधिरोपित जुर्माना 50/- रुपए से अधिक नहीं होता।
- (5) आर्थिक अपराधों और सामाजिक विधियों के अपराधों की बाबत कार्यवाहियाँ जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, जब तक कि ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति द्वारा मदद न मांगी जाए :

परन्तु अध्यक्ष किसी समुचित मामले में ऐसी कार्यवाहियों में भी विधिक सेवा मंजूर कर सकेगा।

- (6) जहाँ विधिक सेवा चाहने वाला व्यक्ति,—
- (क) प्रतिनिधायी या पदीय हैसियत में ही कार्यवाहियों से सम्बद्ध है; या
- (ख) यदि वह कार्यवाहियों में औपचारिक पक्षकार है;

कार्यवाहियों के परिणाम से तात्त्विक रूप से सम्बद्ध नहीं है और उचित प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति के फलस्वरूप उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य नहीं है।

कुछ मामलों में विधिक सेवाएं मंजूर की जा सकती हैं।

15. साधन के मानदंड के बावजूद विधिक सेवा —

- (क) महान लोक महत्व के मामलों में; या
- (ख) विशेष मामले में, जिसके कारण लेखबद्ध किए जाएंगे, यदि अन्यथा विधिक सेवाओं के योग्य समझा जाए।

विधिक सेवा अधिवक्ता को संदेय मानदेय

16. (1) विधिक सेवा अधिवक्ता को ऐसा मानदेय दिया जाएगा जो समिति द्वारा नियत किया जाए।

(2) कोई भी विधिक सेवा अधिवक्ता जिसे कोई मामला या तो विधिक सलाह के लिए या विधिक सेवाओं के लिए समनुदिष्ट किया जाता है, सहायताप्राप्त व्यक्ति से अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से कोई फीस या पारिश्रमिक चाहे, नकद या वस्तु के रूप में या धन के रूप में या अन्यथा कोई अन्य लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

(3) विधिक सेवा अधिवक्ता जिसने अपना समनुदेशन पूरा कर लिया है, सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से की गई विधिक कार्यवाही के संबंध में किए गए काम की रिपोर्ट के साथ-साथ उसे देय मानदेय की रकम दर्शाने वाला एक विवरण समिति के सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो सम्यक् समीक्षा के बाद उसे संदेय शुल्क और व्यय की मंजूरी प्रदान करेगा। तथापि, विधिक सेवा अधिवक्ता को पूर्णतया या भागतः मानदेय का अधिक्यजन करने की छूट होगी। विधिक सेवा अधिवक्ता को संदेय धनराशि के बारे में विवाद होने पर मामला अध्यक्ष के समक्ष विनिश्चय के लिए पेश किया जाएगा।

सहायता प्राप्त व्यक्ति के कर्तव्य

17. (1) विधिक सेवा चाहने वाला व्यक्ति ऐसी किसी अध्यक्ष या निदेश का जो उसे समिति के सचिव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा दिया जाए, विधिक सेवा के लिए आवेदन किए जाने की तारीख से तब तक पालन करेगा जब तक वह उसे प्रदान की गई विधिक सेवा का उपभोग करता है।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति यहाँ उपाबद्ध प्रारूप में एक वचनबंध निष्पादित करेगा कि वह न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में ऐसी डिक्ली या आदेश पारित किए जाने की दशा में, जिसके द्वारा उसे लागत या अन्य धनीय प्रसुविधा या लाभ दिलवाया जाए, वह समिति को प्रतिपूर्ति के रूप में समिति द्वारा उसे विधिक सेवा प्रदान करने में उपगत समस्त लागत, प्रचार और व्यय का प्रतिसंदाय करेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति करने के लिए वह समिति के सचिव को प्राधिकृत करेगा। इस प्रकार वसूल किए गए खर्चें प्रभार और व्यय समिति की निधि में जमा किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक सहायता प्राप्ति व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि समिति द्वारा या उसे विधिक सहायता देने वाले विधिक सेवा अधिवक्ता द्वारा अपेक्षित किए जाने पर समिति के कार्यालय में उपस्थित होगा और पूरी तथा सही जानकारी देगा और संबंधित विधिक सेवा अधिवक्ता के समक्ष पूरी बात प्रकट करेगा तथा जब कभी आवश्यक हो अपने खर्च पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

विधिक सेवाओं का वापस लिया जाना

18. (1) समिति स्वप्रेरणा से या अन्यथा निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी सहायता प्राप्त व्यक्ति को दी गई विधिक सेवा को वापस ले सकेगी, अर्थातः—

(क) यह पाए जाने की दशा में कि सहायता प्राप्त व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हैं अथवा यह कि उसने दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा विधिक सेवा अभिप्राप्त की हैं;

(ख) सहायता प्राप्त व्यक्ति की परिस्थितियों में कोई तात्त्विक परिवर्तन होने पर;

(ग) विधिक सेवा प्राप्त करने के दौरान सहायताप्राप्त व्यक्ति की ओर से कोई अवचार, उपापराध या ठपेक्षा किए जाने पर;

(घ) सहायताप्राप्त व्यक्ति के समिति के साथ या समिति द्वारा समनुदिष्ट विधिक सेवा अधिवक्ता के साथ सहयोग न किए जाने की दशा में;

(ङ) सहायताप्राप्त व्यक्ति द्वारा समिति द्वारा समनुदिष्ट अधिवक्ता से भिन्न विधि-व्यवसायी किए जाने की दशा में;

(च) सिविल कार्यवाहियों के सिवाय जिनमें अधिकार या दायित्व बना रहता है, सहायताप्राप्त व्यक्ति की मृत्यु होने पर;

(छ) विधिक सेवा के आवेदन या प्रशंगत मामले को प्रक्रिया के या विधिक सेवा के दुरुपयोग के रूप में पाए जाने की दशा में;

परन्तु विधिक सेवा, सहायताप्राप्त व्यक्ति को या उसकी मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि को यह कारण बताने के लिए कि विधिक सेवा वापस क्यों न ली जाए, उसकी सम्यक् सूचना दिए बिना वापस नहीं ली जाएगी।

(2) जहाँ उपरोक्त उप विनियम (1) में वर्णित आधारों पर विधिक सेवा वापस ले ली जाए, वहाँ समिति सहायताप्राप्त व्यक्ति से उसे दी गई विधिक सेवा की राशि वसूल करने की हकदार होगी।

[एफ. 6(2)/96-गालसा]

डा. वी. के. अग्रवाल अपर सचिव

(विनियमन 17 के खण्ड (2) से सुसंगत)

शपथ-पत्र

मैं,-----आयु

लगभग-----वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री-----

निवासी—  
एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिदान करता हूँ और निम्नलिखित कथन करता हूँ कि :—

1. (क) मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का सदस्य हूँ।
- (ख) मैं मानव प्राणियों में व्यापार या बैंगार से पीड़ित हूँ।
- (ग) मैं स्त्री/बालक होनेके नाते विधिक सेवा का पात्र हूँ।
- (घ) मैं मानसिक तौर पर बीमार हूँ अथवा अन्यथा निःशक्त व्यक्ति हूँ।
- (ङ) मैं विशाल विपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूचाल या औद्योगिक विपत्ति से पीड़ित होने के कारण अनर्ह अभाव की परिस्थितियों में हूँ।
- (च) मैं एक औद्योगिक कर्मकार हूँ।
- (छ) मैं अभिरक्षा में हूँ।
- (ज) मैं समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 18,000/- (अठारह हजार रुपए) से कम है।

( जो लागू न हो उसे काट दीजिए )

2. मैं किसी भी अधपेक्षा और निदेश का पालन करूंगा जो उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव या किसी सदस्य द्वारा दिया जाए।

3. मैं समिति द्वारा दिए जाने वाले विधिक सेवा अधिवक्ता के सामने सभी तथ्यों की पूरी और सही जानकारी पेश करूंगा।

4. मैं—

(क) —————

में—

के निर्णय के विरुद्ध अपील में

(ख) —————

के लिए रिट अधिकारिता में माननीय उच्चतम न्यायालय में जाना चाहता हूँ।

( जो लागू न हो उसे काट दीजिए )

5. मैं एतद्वारा सहमत हूँ कि न्यायालय द्वारा मेरे पक्ष में कोई डिफ्री या आदेश पारित दिए जाने की दशा में जिसके द्वारा मुझे इसकी खर्चा या अन्य धनीय प्रनुविधा या लाभ दिलावाया जाए, मैं समिति को प्रतिपूर्ति के रूप में मुझे विधिक सेवा प्रदान करने में समिति द्वारा उपगत समस्त व्ययों प्रभार और व्यय का प्रतिगंदाय करूंगा। मैं एतद्वारा उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव को ऐसे समस्त कार्य और बातें करने के लिए भी प्रधिकृत करता हूँ जो मुझे संदत्त किए जाने के लिए डिफ्री या आदेशित रकम की वसूली या आपन के लिए तथा ऊपरवर्णित प्रयोजन के लिए उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक हों।

6. मैं सहमत हूँ कि यदि किसी भी प्रक्रम पर समिति द्वारा यह समझा जाए कि मेरे मामले में लोक अदालत के माध्यम से सुलह या समझौता कराया जा सकता है तो मेरा मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लोक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध कर लिया जाए।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी—  
अभिसाक्षी एतद्वारा सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 से 4 की अन्तर्बस्तु मेरी जानकारी में सही और ठीक है; उनमें अंकित कुछ भी लिखा नहीं है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी सहायता करे।

आज तारीख—

मास—

वर्ष—

को—में स्थापित।

अभिसाक्षी

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1996

G.S.R. 336 (E):—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Legal Services Authorities Act, 1987, the Central Authority hereby makes the following regulations, namely :—

Short title and commencement.

1. (1) These regulations may be called the Supreme Court Legal Services Committee regulations, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In these Regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1989 (39) of 1987;

(b) "Central Authority" means the National Legal Services Authority constituted under Section 3 of the Act;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Supreme Court Legal Services Committee;

(d) "Committee" means the Supreme Court Legal Service Committee;

(e) "Legal Service Advocate" means an Advocate who has been assigned any work related to legal service;

(f) "Legal Service Counsel-cum-Consultant" means an Advocate appointed as legal service Counsel-cum-Consultant by the Committee;

(g) "Member" means a member of the Committee;

(h) "Secretary" means the Secretary of the Committee appointed under sub-section (3) of Section 3A of the Act.

General effect of vesting.

3. On and from the date of commencement of these regulations,—

(1) All the assets, liabilities, rights, title and interest of the erstwhile Supreme Court Legal Aid Committee stand transferred to, and vest in, Supreme Court Legal Services Committee;

(2) The staff who have been serving under the erstwhile Supreme Court Legal Aid Committee shall

be deemed to be working for the Supreme Court Legal Services Committee;

- (3) The Committee shall pay the fee bills submitted by the Legal Aid panel Lawyers for their professional services and all other dues incurred by and which have been pending before the erstwhile Supreme Court Legal Aid Committee after verifying the same;
- (4) The Committee shall become successor of the erstwhile Supreme Court Legal Aid Committee and will honour all the commitments made by the erstwhile Supreme Court Legal Aid Committee in so far as providing legal aid in cases before Supreme Court of India, is concerned. No asset or liability of the Supreme Court (Middle Income Group) Legal Aid Committee will devolve on the Committee, but the Committee may extend such facilities of its establishment to the said Supreme Court (Middle Income Group) Legal Aid Committee as the chairman may approve.

**The term of office and other conditions relating thereto of the members of the Committee.**

4. (1) The term of the office of a member of the Committee, other than ex-officio member, shall be two years.

(2) Where a person is nominated as a ex-officio member, such person shall cease to be a member of the Committee if he ceases to hold the post or office by virtue of which he has been nominated as a ex-officio member.

(3) Any vacancy in the office of a member of the Committee shall be filled up in the same manner as the originally appointed member and the person so nominated shall continue to be a member for the remaining period of term of office of that member in whose place he has been nominated.

(4) A member other than ex-officio member shall be eligible for nomination for not more than two term.

**Powers and functions of the Committee.**

(5) The powers and functions of the Committee shall be:—

- (a) To administer and implement the legal services programme in so far as it relates to the Supreme Court of India and for this purpose take all such steps as may be necessary and to act in accordance with the directions issued by the Central Authority from time to time;
- (b) To receive and scrutinise applications for legal services and to decide all questions as to the grant of or withdrawal of legal service;
- (c) To maintain panels of advocates on record and of senior advocates in the Supreme Court for giving the legal advice;
- (d) To decide all matters relating to payment of honorarium, costs, charges and expenses of legal services to the advocates on record and to senior advocates of the Supreme Court;
- (e) To prepare and submit returns, reports and statistical information in regard to the legal services

programme to the Central Authority.

**Functions and powers of the Chairman.**

6. (1) The Chairman of the Committee shall be in over all charge of administration and implementation of the programmes of the Committee:

Provided that the Chairman shall not directly concern any question as to grant or withdrawal of legal service to any person.

(2) The Chairman shall cause the meetings of the Committee convened through the Secretary at least once in a period of three months.

(3) The Chairman shall preside over the meetings of the Committee.

(4) The Chairman shall have all the residuary powers of the Committee.

**Terms and conditions of service of the Secretary.**

7. (1) The term of the Office of the Secretary shall be three years.

(2) The Secretary shall be entitled to receive such honorarium as fixed by the Chairman.

(3) The Secretary can be removed at any time by the Chief Justice of India.

**Functions and powers of the Secretary.**

8. (1) The Secretary shall be the principal officer of the Committee and shall be the custodian of all assets, accounts, records and funds at the disposal of the Committee.

(2) The Secretary shall maintain or cause to be maintained true and proper accounts of the receipts and disbursement of the funds of the Committee.

(3) The Secretary shall convene meetings of the Committee with the previous approval of the Chairman and shall also attend meetings and shall be responsible for maintaining a record of the minutes of the proceedings of the meetings.

**Meetings of the Committee.**

9. (1) The Committee shall meet at least once in three months on such date, and at such place as the Chairman may direct.

(2) The Chairman shall preside over the meetings of the Committee and in the absence of the Chairman, a person chosen by the members present from amongst themselves shall preside over the meetings of the Committee.

(3) The minutes of the proceedings of each meeting shall be truly and faithfully maintained by the Secretary and such minutes shall be open to inspection at all reasonable times by the members of the Committee. A copy of the minutes shall, as soon as may be, after the meeting, be forwarded to the Executive Chairman of the Central Authority.

(4) The quorum for the meeting shall be four including the Chairman.

(5) All questions which come up before any meeting of the Committee shall be decided by a majority of votes of the members present and voting, and in case of a tie, the Chairman or the person presiding shall have the right to exercise a second or casting vote.

**Funds, audit and accounts of the Committee.**

10. (1) The Committee shall maintain a Fund to be

called Supreme Court Legal Services Committee Fund to which shall be credited,—

- (a) such amounts as may be allocated and granted to it by the Central Authority;
- (b) all such amounts received by the Committee by way of donations;
- (c) all such amounts by way of costs, charges and expenses recovered from the persons to whom legal service is provided or the opposite party.

(2) All the amounts credited to the said Fund, shall be deposited in a nationalised bank.

*Explanation :—*In the sub-regulation "nationalised bank" means a corresponding new bank as defined in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer on Undertakings) Act, 1980.

(3) For the purpose of meeting incidental minor charges, such as Court-fee stamps and expenditure necessary for obtaining copies of documents etc., a permanent advance of Rupees two thousand five hundred shall be placed at the disposal of the Secretary of the Committee.

(4) All expenditure on legal service, accommodation and staff of the Committee as also expenditure necessary for carrying out the various functions of the Committee shall be met out of the Funds of the Committee and in accordance with the prior approval of the Chairman.

(5) The funds of the Committee may be utilised for meeting the expense incurred on or incidental to travels undertaken by the Chairman or other members of the Committee or the Secretary in connection with legal services activities. The travelling allowance and the dearness allowance payable to the Chairman, the ex-officio members and the Secretary shall be such as to which they are entitled by virtue of their respective Offices held.

(6) The Secretary of the Committee and one member of the Committee designated by the Chairman for this purpose shall jointly operate the bank accounts of the Committee in accordance with the directions of the Chairman.

(7) The Committee shall cause to be kept and maintained true and correct accounts of all receipts and disbursements and furnish quarterly returns to the Central Authority.

(8) The accounts of the Committee shall be audited annually by a qualified Auditor and submitted to the Central Authority.

#### **Application for legal services.**

11. (1) Any person deserving legal service for bringing or defending any action in the Supreme Court may make an application in writing in that behalf. However, if the applicant is illiterate or is not in a position to write, the Secretary or an officer of the Committee shall record his verbal submissions and obtain his thumb impression/signature on the record and such record will be treated as his application.

(2) The Committee shall maintain a register of applications wherein all applications for legal service shall be entered and registered date wise and the action taken on such applications shall be noted against the entry relating to such

applications.

#### **Disposal of applications.**

12. (1) On receipt of an application for legal service mentioned in Regulation 11, the Secretary shall first cause the eligibility of the applicant as per the provisions of the Act read with the rules, examined and determined.

(2) If the applicant satisfies the eligibility criteria, the Secretary shall proceed to examine the merit of his application. For examining the merits of the application, the Secretary may take the assistance of legal services advocates or other advocates willing to provide free legal advice. The Secretary may also take the advice of the Legal Service Counsel-cum-Consultant employed by the Committee. The Secretary shall not be precluded from seeking more than one opinion if any particular case requires in-depth examination.

(3) In case the applicant satisfies the eligibility criteria and also has merit in his application, the Secretary shall proceed to decide the mode of legal service.

(4) An application for the grant of legal services in any matter if it is not found fit may be rejected, for the reasons to be recorded in writing, by the Secretary.

(5) In case of refusal for the grant of legal services, the Secretary shall inform the applicant in writing of such refusal.

(6) The applicant whose application for grant of legal services has been rejected may prefer an appeal before the Chairman for a decision.

#### **Modes of Legal Services.**

13. Legal services to be provided may include any one or more of the following:—

- (a) payment of court-fees, process fees and all other charges payable or incurred in connection with any legal proceedings;
- (b) charges for drafting, preparing and filling of any legal proceedings and representation by a legal practitioner in legal proceedings;
- (c) cost of obtaining and supply of certified copies of judgments, orders and other documents in legal proceedings;
- (d) cost of preparation of paper book (including paper, printing and translation of documents) in legal proceedings and expenses incidental thereto.

#### **Legal Services not to be provided in certain cases.**

14. Legal services shall not be given in the following cases, namely :—

- (1) Proceedings wholly or partly in respect of —
  - (a) defamations; or
  - (b) malicious prosecution; or
  - (c) a person charged with contempt of court proceedings; and
  - (d) perjury.
- (2) Proceedings relating to any election.
- (3) Proceedings incidental to any proceedings referred to in sub-regulations (1) and (2).
- (4) Proceedings in respect of offences where the fine imposed is not more than Rs. 50/-.

(5) Proceedings in respect of economic offences and offences against social laws, such as, the Protection of Civil Rights Act, 1955, and the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 unless in such cases the aid is sought by the victim:

Provided that the Chairman may in an appropriate case grant legal services even in such proceedings.

(6) Where a person seeking legal services,—

- (a) is concerned with the proceedings only in a representative or official capacity; or
- (b) if a formal party to the proceedings, not materially concerned in the outcome of the proceedings and his interests are not likely to be prejudiced on account of the absence of proper representation.

#### **Legal Services may be granted in certain cases.**

15. Irrespective of the means test, legal service may be granted—

- (a) in cases of great public importance; or
- (b) in a special case, reasons for which to be recorded in writing, is considered otherwise deserving of legal services.

#### **Honorarium payable to legal service advocate.**

16. (1) The legal service advocate shall be paid such honorarium as may be fixed by the Committee.

(2) No legal service advocate to whom any case is assigned either or legal advice or for legal services shall receive any fee or remuneration whether in cash or in kind or any other advantage, monetary or otherwise, from the aided person or from any other person on his behalf.

(3) The legal service advocate who has completed his assignment, shall submit a statement showing the honorarium due to him together with the report of the work done in connection with the legal proceeding conducted by him on behalf of the aided person, to the Secretary of the Committee, who shall, after due scrutiny sanction the fee and expenses payable to him. It will, however, be open to the legal service advocate to waive the honorarium wholly or partially. In case of any dispute on the quantum payable to the legal service advocate, the matter shall be placed before the Chairman for decision.

#### **Duties of aided person.**

17. (1) A person seeking legal services shall comply with any requisition or direction that may be made upon him by the Secretary of the Committee or any of its members from the date the application for legal services is made till he enjoys the legal services granted to him.

(2) Every such person shall execute an undertaking in the form annexed hereto that in the event of the Court passing a decree or order in his favour awarding costs to him or other monetary benefit or advantage, to repay by way of reimbursement to the Committee all costs, charges and expenses incurred by the Committee in giving him legal service. For effecting such reimbursement, he shall authorise the Secretary of the Committee. The costs, charges and expenses so recovered shall be credited to the Fund of the Committee.

(3) Every aided person or his representative shall attend the office of the Committee as and when required by the

Committee or by the legal service advocate rendering legal aid to him and shall furnish full and true information and shall make full disclosure to the legal service advocate concerned and shall attend the Court, as and when required, at his own expense.

#### **Withdrawal of legal services.**

18. (1) The Committee may either on its own motion or otherwise withdraw legal services granted to any aided person in the following circumstances, namely:—

- (a) in the event of it being found that the aided person was possessed of sufficient means or that he obtained legal service by misrepresentation or fraud;
- (b) in the event of any material change in the circumstances of the aided person;
- (c) in the event of any misconduct, misdemeanor or negligence on the part of the aided person in the course of receiving legal service;
- (d) in the event of the aided person not co-operating with the Committee or with the legal service advocate assigned by the Committee;
- (e) in the event of the aided person engaging a legal practitioner other than the one assigned by the Committee;
- (f) in the event of death of the aided person, except in the case of civil proceedings where the right or liability survives;
- (g) in the event of the application for legal service or the matter in question is found to be an abuse of the process of law or of legal services;

Provided that legal service shall not be withdrawn without giving due notice thereof to the aided person or to his legal representatives in the event of his death, to show cause as to why the legal service should not be withdrawn.

(2) Where the legal services are withdrawn on the grounds set out in clause (a) of sub-regulation (1) above, the Committee shall be entitled to recover from the aided person the amount of legal service granted to him.

[F. 6(2)/96-NALSA]

DR. V.K. AGARWAL, Addl. Secy.

[Relevant to clause (2) of Regulation 17]

#### **A F F I D A V I T**

I, \_\_\_\_\_, aged about \_\_\_\_\_ years, son of/daughter of/wife of Shri \_\_\_\_\_ Resident of \_\_\_\_\_ do hereby solemnly affirm and state as under :—

- 1. (a) I belong to a member of a Scheduled Castes/ Scheduled Tribes.
- (b) I am a victim of trafficking in human beings or a beggar.
- (c) I am eligible for legal service as I am a woman/ child.
- (d) I am a mentally ill or otherwise disabled person.



- (e) I am a person under circumstances of undeserved want being a victim of a mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster.
- (f) I am an industrial workman.
- (g) I am in custody.
- (h) My annual income from all sources is below Rs. 18,000/- (rupees eighteen thousand only).

*(Delete whatever is not applicable)*

2. I shall comply with any requisition and direction that may be made by the Secretary or any of the members of the Supreme Court Legal Services Committee.
3. I shall furnish full and true information of all facts of my case to the legal service advocate to be provided by the Committee.
4. I seek to approach the Honourable Supreme Court of India—
  - (a) in appeal from the Judgement of \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_
  - (b) in writ jurisdiction for \_\_\_\_\_

*(Delete whatever is not applicable)*

5. I hereby agree that in the event of the Court passing a

decree or order in my favour awarding cost to me or other monetary benefit or advantage, I shall repay by way of reimbursement to the Committee all Costs, Charges and expenses incurred by the Committee in giving me legal service. I hereby also authorise the secretary of the Supreme Court Legal Services Committee to do all such acts and things as may be necessary for recovery or realisation of the amount decreed or ordered to be paid to me and to reimburse the same for the above mentioned purpose.

6. I agree that my case be listed before Lok Adalat in Honourable Supreme Court, if at any stage it is considered by the Committee that my matter can be reconciled or settled through Lok Adalat.

DEPONENT

Verification :

I, Shri/Shrimati/Kumari \_\_\_\_\_ the above named Deponent do hereby verify that the contents of the Paragraphs 1 to 4 are true and correct to my knowledge; nothing stated therein is false and nothing has been concealed. So help me God.

Verified on this day of \_\_\_\_\_, 199  
at \_\_\_\_\_.

DEPONENT

1856 GI/96-2

